महत्वपूर्ण एवं खास

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर

सी -60 कमांडो सर्च कार्यवाही अब भी जारी

राजनांदगांव/गढ़चिरौली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ महाराष्ट्र पुलिस की सी-60 यूनिट और नक्सिलयों के बीच हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की गुप्त जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की सी-60 कमांडो टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। जब नक्सलियों ने खुद के पुलिस से घिरा देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इस एनकाउंटर में 13 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनके शवों को बरामद कर लिया गया है। गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल ने भी इसकी पुष्टि की है।

प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8 प्रतिशत पहुंची, 14 जिलों में भी पॉजिटिविटी दर 8 प्रतिशत या इससे कम

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर अब 8 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राज्य के 14 जिलों में भी पॉजिटिविटी दर घटकर 8 प्रतिशत या इससे कम हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी पॉजिटिविटी दर 15 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों से विभिन्न जिलों में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। राजनांदगांव, सुकमा और बीजापुर जिले में अभी संक्रमण की दर 2 प्रतिशत, कबीरधाम और कांकेर में 3 प्रतिशत, दुर्ग में 4 प्रतिशत, कोरबा और नारायणपुर में 5 प्रतिशत, बिलासपुर में 6 प्रतिशत, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, जशपुर और दंतेवाड़ा में 7 प्रतिशत तथा बेमेतरा में 8 प्रतिशत है। 20 मई की स्थिति में बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, बस्तर और कोंडागांव में संक्रमण की दर 9 प्रतिशत है। प्रदेश के शेष जिलों में पॉजिटिविटी दर 9 प्रतिशत से अधिक है।

डीएपी खाद की कीमत कम करने पर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया

रायपुर (आरएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा डीएपी खाद की कीमत करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। डा. रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए डीएपी खाद पर राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाताओं को अब 2400 की जगह 1200 में डीएपी खाद की बोरी मिलेगी। इस कल्याणकारी फैसले के लिए छत्तीसगढ़ के किसान भाईयों की ओर से डा. सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

किसान न्याय योजना, गोधन योजना तथा गौठान समिति को भुगतान पर कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि छ.ग.प्रदेश के जागरूक एवं संवदेनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार 29 दिनों में प्रदेश में महामारी को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है जो सराहनीय है तथा हर जिला, तहसील, गांव में सत्त नजर रखकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करके उनसे काम लेने की बात में बघेल जी विश्वास रखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफसीजन 2020-21 की पहली किश्त का 1500 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को 7.17 करोड़ रूपये तथा गोठान समितियां महिला स्व. सहायता समूह को 3.6 करोड़ रूपया की राशि ग्रामीणों के बीच लगभग 25.23 करोड़ रूपये राशि वितरीत की गई है।

किसानों को खरीफ की तैयारियों के लिए 1500 करोड़ रूपए की सौगातः मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों के खाते में अंतरित की

रायगढ़ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में ऑनलाईन अंतरित की। किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रूपए आदान सहायता के रूप में चार किस्तों में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत सहित मंत्रीमंडल के सभी सदस्यों ने इस

मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यगीत से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72 हजार ग्रामीणों, पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के मध्य गौठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रूपए का भी अंतरण किया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रायगढ़ जिले के 01 लाख 01 हजार 53 किसानों को 319 करोड़ 99 लाख रुपये मिलेंगे। आज पहली किश्त के रूप में 86 करोड़ 87 लाख 98 हजार रुपये अंतरित किये गये। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के तहत पिछले चार चक्रों का भुगतान भी किया गया। इसके अंतर्गत जिले के पशुपालकों को 01 करोड़ 01 लाख 5 हजार 738 रुपये अंतरित किये गये। यह पूरे प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती-किसानी बेहतर हुई है। सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है। इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम, पीड़ितों के उपचार एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने इस मौके पर कोरोना टीकाकरण की स्थिति, समाज के अंत्योदय एवं गरीब परिवारों को दो महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, कोविड महामारी के चलते बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के निःशुल्क प्रबंध एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई महतारी दुलार योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई।

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले से विधायक धरमजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर भीम सिंह, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी, उप संचालक कृषि एल.एम.भगत, उप पंजीयक सहकारिता सुरेंद्र गोंड सहित अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित हुये।

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़िया आग बुझाने में जुटी

रायपुर (आरएनएस)। भनपुरी स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सुचना पर फायर ब्रिगेड की 06 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुटी हुई है। घटना शाम 04 बजे के आसपास की बतायी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार खमतराई थानाक्षेत्र में शुक्रवार को भनपुरी स्थित कोलबिंया पेट्रो केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सुचना मिलते ही पुलिस की टीम एवं फायर ब्रिगेड की 06 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह से एक एक टैंकर में विस्फोट हो गया है जिसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में विस्फोट होने की आवाज फैक्ट्री से आती रही। आग इतना भीषण था कि आग की लपटे काफी ऊॅची उठने लगी इस वजह से आसमान में दुर से ही काल धुआं का गुब्बार दिखा दे रहा था। जिसे देखकर बड़ी संख्या में आस-पास के लोग फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर वीडियों बनाने लगे। जिन्हें पुलिस ने फैक्ट्री के आस-पास से दुर हटाया। वहीं दमकलकर्मी मौके पर आग को बुझाने के लिये चाररों ओर से पानी के बौछारे कर रहे है। आयल फैक्ट्री से आग लगने के बाद केमिकल बहकर सड़क तक आ गया। आग लगने की वजह से अभी तक कोई जान-माल का नुकसान होने की सुचना नही मिली है व आग कैसे लगा यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। आग की वजह से केमिकल फैक्ट्री में लाखों का नुकसान होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने दी दरिमा-अम्बिकापुर में माँ महामाया एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, क्षेत्रवासियों जताया आभार

» खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के प्रयासों से माँ महामाया एयरपोर्ट उन्नयन के लिए 43.56 करोड़ रुपए मंजूर

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सफर शुरू करने का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने सरगुजा संभाग के दरिमा-अम्बिकापुर में माँ महामाया एयरपोर्ट उन्नयन के लिए 43 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासकीय मंजूर प्रदान की है। हवाई सेवा शुरू करने का यह सपना साकार हो रहा है क्षेत्रीय

विधायक और मंत्री अमरजीत सिंह भगत के अथक प्रयासों से, जिन्होंने क्षेत्रीय जन मानस की मांग और आवश्यकता को देखते हुए दरिमा-अम्बिकापुर को माँ महामाया के नाम से एयरपोर्ट बनाने के लिए अहम भूमिका निभाया और मुख्यमंत्री के सहयोग से एयरपोर्ट निर्माण के लिए साढ़े 43 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति मिली।

इस राशि की स्वीकृति से माँ महामाया एयरपोर्ट के निर्माण का सम्पूर्ण कार्य तय समय-सीमा में पूरा होकर सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित माँग एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्बिकापुर-सरगुजा को नई पहचान मिलेगी।

गौरतलब है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत माँ महामाया एयरपोर्ट दरिमा के उन्नयन के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं। वे लगातार एयरपोर्ट पहुंचकर विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते थे।

दरिमा-अम्बिकापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए आज जो इतनी बड़ी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, वह मंत्री अमरजीत भगत की कार्य कुशलता तथा प्रतिबद्धता का ही प्रतिफल है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से सरगुजा संभाग की जनता को हवाई सफर की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत के प्रति आभार जताया है।

9 प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए

» केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने की विस्तृत चर्चा

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज आयोजित 9 प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों की वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने सहभागिता की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन के साथ ही ब्लैक फंगस पर भी चर्चा की गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेजेंटेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की स्थिति, कोरोना के प्रसार और रिकवर हुए मरीजों का उल्लेख किया गया। जिस विषय पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 8 दिनों से संक्रमण का प्रभाव

कम होता दिखाई दे रहा है और नए मरीजों की तुलना में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ की दैनिक औसत टेस्टिंग संतोषजनक चल रही है, जनवरी महीने में यह औसत संख्या 22,761 थी लेकिन मई महीने तक हमनें 66,542 औसत टेस्टिंग प्रतिदिन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने क्युमल्टीव टेस्ट प्रति 10 लाख की स्थिति को भी संतोषजनक बताया, टेस्टिंग और टीकाकरण जैसे कुछ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का औसत भारतीय औसत से ज्यादा दिख इसके उपरांत भी सिंहदेव ने कहा की हम पूरे प्रयास करेंगे जिससे कहीं कोई कमी बाकी न रहे।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 गवर्नमेंट लैब और 6 प्राइवेट लैब में ट्रू नेट जांच की सुविधा है और 11 गवर्नमेन्ट लैब व 5 प्राइवेट लैब्स में आरटीपीसीआर की भी टेस्टिंग है। इसके साथ ही 5 अन्य लैब छत्तीसगढ़ में स्थापित होने जा रही हैं। पॉजिटिविटी दर का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 1 मार्च को छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट न्यूनतम स्तर पर थी लेकिन 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सबसे खराब समय रहा जब 12 अप्रैल को 29.51 और 25 अप्रैल को 30.78 का औसत पाजिटिविटी रेट पूरे प्रदेश में था। इसके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अथक परिश्रम किया है। कल के डेटा अनुसार जो केसेस आये हैं उनमें पॉजिटिविटी रेट घट के संतोषजनक 7.83 पर आया है हमारा लक्ष्य पहला 5 प्रतिशत राज्य के औसत को लाना है और फिर 3 प्रतिशत के नीचे लेकर जाना है इस टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने बताया कि होम आइसोलेशन से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक की जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें एम्स के साथ 37 डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल और 154 कोविड केअर सेन्टर वर्तमान में स्थापित है।

छत्तीसगढ़ को प्राप्त टीकों की बूंद-बूंद का उपयोग, राज्य में वेस्टेज डोज का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत राज्य को प्राप्त टीकों की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य को 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लिए 07 लाख 97 हजार 110 डोज़ मिली थी, जिसमें से 06 लाख 66 हजार 101 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 01 लाख 25 हजार 970 डोज़ का टीकाकरण जारी है। इस तरह इस आयु वर्ग के लिए प्राप्त टीकों में वेस्टेज डोज की संख्या केवल 5039 रही, जो कि प्राप्त टीकों का मात्र 0.6 प्रतिशत है।

इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में राज्य को 68 लाख 40 हजार 210 डोज़ मिल चुकी है। इसमें से 61 लाख 67 हजार 632 डोज का उपयोग किया जा चुका है। वर्तमान में बची हुई 06 लाख 16 हजार 970 डोज से टीकाकरण किया जा रहा है। इस आयु वर्ग में वेस्टेज डोज की संख्या केवल 56 हजार 608 है, जो कि प्राप्त डोज का केवल 0.8 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर डोज के वेस्टेज औसत 2 प्रतिशत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दोनों आयु वर्गों में वेस्टेज का प्रतिशत बहुत ही कम है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए सुपर कम्पोस्ट खाद लांच की

» उच्च जैविक विशेषता वाली सुपर कम्पोस्ट खाद की कीमत 6 रूपए किलो

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कम्पोस्ट खाद को राज्य के किसानों के लिए लॉच किया। किसानों को रियायती दर पर उच्च जैविक विशेषताओं वाली सुपर कम्पोस्ट खाद सहकारी समितियों में 02 किलो, 05 किलो और 30 किलो के बैग में मिलेगी। जिसका न्यूनतम

मूल्य 6 रूपए किलो है। गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 06 लाख रूपए की लाभांश राशि का भी अंतरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यगण उपस्थित थे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में पशुधन संरक्षण, ग्रामीणों, पशुपालकों और किसानों को अतिरिक्त आय के साथ - साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत् गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर क्रय कर महिला समूहों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने के शुरूआत की गई। राज्य में निर्मित 5586 गौठानों में अब तक 47.65 लाख चिंटल गोबर क्रय किया जा चुका है, जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को 95 करोड़ 31 लाख रूपए का भुगतान किए गए हैं। गौठानों में अब तक 2 लाख 26 हजार 316 चिंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन तथा एक लाख 21 हजार 172 चिंटल खाद का विक्रय किसानों एवं शासकीय विभागों को किया गया है। गौठानों में अब महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुपर कम्पोस्ट खाद भी तैयार की जाने लगी है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री त्यागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कृ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

होम आइसोलेटेड मरीज को अस्पताल शिफ्टिंग के दौरान अपनी आइसोलेशन अवधि के मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ले जाना होगा साथः कलेक्टर भीम सिंह

» कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना संक्रमण को लेकर गत दिवस स्वास्थ्य विभाग तथा कोविड अस्पताल संचालकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली। कलेक्टर सिंह ने बैठक में कोरोना प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की गहन समीक्षा की। उन्होंने सर्वप्रथम होम आईसोलेशन मॉनिटरिंग की समीक्षा करते हुये कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन के अनुसार ही होम आईसोलेशन दिया जाना है। जो मरीज क्राइटेरिया में नहीं आते उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करना है। होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों का नियमित फालोअप करना है। जिससे मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिरे या उसकी स्थिति बिगड़े तो तत्काल उसे अस्पताल शिफ्ट किया जा सके।

कलेक्टर सिंह ने होम आईसोलेशन टीम से कहा कि आईसोलेशन में रह रहे मरीजों को नियमित रूप से ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल टेम्परेचर तथा पल्स रीडिग की दिन में चार बार रीडिंग लेकर जानकारी रखनी है तथा मरीज यदि अस्पताल शिफ्ट होता है तो यह जानकारी वाली शीट साथ में लेकर अस्पताल जाना है जिससे इलाज करने वाले चिकित्सक को मरीज की हिस्ट्री पता चल सके और उसके अनुसार मरीज का इलाज तय किया जा सके।

कलेक्टर सिंह ने पोस्ट कोविड लक्षणों के उपचार के संबंध में पोस्ट कोविड ओपीडी तथा मेन्टल हेल्थ केयर ओपीडी जिला अस्पताल में चलाने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने इस दौरान जिले के कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध बेड की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में वेन्टीलेटर तथा बाईपेप मशीनों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होंने विकासखण्ड स्तरीय कोविड केयर सेंटर में भी बाईपेप मशीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। इसके ऑपरेशन संबंधी ट्रेनिंग भी संबंधित अस्पताल स्टाफ को देने के लिये कहा। उन्होंने सभी सीएचसी में 50 बेड हेतु ऑक्सीजन पाईप लाइन लगाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने आने वाली लहर के मद्देनजर जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आने वाली लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे बच्चे भी प्रभावित होंगे। इसको ध्यान में रखते हुये उनके इलाज से जुड़े आवश्यक प्रबंध पहले से तैयारी रखनी है। इस संबंध में उन्होंने नियोनेटल आईसीयू स्थापित करने की दिशा में भी काम करने के लिये कहा।